THE WORLD BANK

Working for a World Free of Poverty

समाचार विज्ञप्ति

समाचार विज्ञप्ति सं. SAR	संपर्क: *दिल्ली में* सुदीप मजूमदार (91 11) 2461-7241 smozumder@worldbank.org *वाशिंगटन में:* एरिक नोरा (202) 458 4735 enora@worldbank.org

विश्व बैंक, भारत के उड़ीसा राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा गरीबी कम करने के उपायों का समर्थन करता है

वांशिंगटन, 1 अगस्त, 2006: भारत में उड़ीसा राज्य के ग्रामीण गरीब एवं वंचित लोग विश्व बैंक के इस 225 मिलियन अमरीकी डालर ऋण/क्रेडिट से लाभान्वित होंगे। यह ऋण सर्वसम्मिलित विकास को बढ़ावा देने और तीव्र गरीबी न्यूनीकरण हासिल करने के लिए इस राज्य द्वारा बनाए गए सुधार कार्यक्रम को सहायता प्रदान करेगा।

आज विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया दूसरा **उड़ीसा सामाजिक–आर्थिक विकास ऋण एवं क्रेडिट** इन सुधारों की सहायता करना जारी रखेगा जिनका लक्ष्य गरीबों के लिए विशेषकर कृति में आय के अवसर बढ़ाना तथा बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुंच में सुधार करना है। इससे सहायता पाने वाले सुधारों का फोकस गरीब किसानों के लिए कृषि उपज, भूमि अधिकारों की सुरक्षा एवं बाज़ार तक पहुंच बढ़ाने, निवेश के माहौल में सुधार करने तथा हाल के वर्षों में हासिल वित्तीय सुधार का सुदृढ़ीकरण करने पर केंद्रित होगा।

अपनी समृद्ध खनिज संपदा, वनों, झीलों, नदियों और दक्षिण–पूर्व एशिया की ओर एक लंबे समुद्र तट के बावजूद उड़ीसा भारत के मुख्य गरीब राज्यों में से एक है। 1990 के दशक की निश्चलता के बाद आर्थिक विकास में हाल के वर्षों में तेजी आई है जिसमें खनन, कृषि और सेवा क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि शामिल है। गत वर्षों के दौरान वास्तविक आर्थिक विकास 8.4 प्रतिशत की औसत पर पहुंच गया है जो अखिल भारतीय औसत से अधिक है और 1990 के दशक की वृद्धि दर से लगभग दोगुनी है।

विश्व बैंक के लीड ईकॉनामिस्ट और को–टीम लीडर वी.जे. रविशंकर के शब्दों में, *"उच्च कृषि वृद्धि दर खासतौर पर स्वागत करने लायक है क्योंकि यह अभी भी इस राज्य में सभी कामगारों से 80 प्रतिशत से अधिक कामगारों को रोजगार मुहैया करा रही है। कृषि की उपज और आर्थिक प्रतिफलों में सुधार करना इस प्रयास का केंद्रबिंदु है और ग्रामीण गरीबों के लिए इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।"*

यह परियोजना वित्त, वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक जवाबदेही सुधारों के लिए भी सहायता प्रदान करेगी जिनमें साख को बेहतर बनाने के लक्ष्य से भ्रष्टाचार–रोधक उपाय एवं सार्वजनिक प्रापण–तंत्र में सुधार शामिल हैं। यह उच्च प्राथमिकता वाले विकास व्ययों के लिए अतिरिक्त वित्तीय गुंजाइश भी पैदा करेगी, और सरकार के वित्तीय संसाधनों के अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं पारदर्शी प्रबंधन को बढ़ावा देगी।

उड़ीसा में भारत की जनजातियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी मौजूद है जो इनकी कुल आबादी का 22.2 प्रतिशत है और गरीबों की कुल संख्या में 40 प्रतिशत से भी अधिक है।

विश्व बैंक के सीनियर ईकॉनामिस्ट और को–टीम लीडर मारिना वेस के शब्दों में, *"अनूसूचित जनजातीय आबादी का यह सापेक्ष नुकसान उड़ीसा में गरीबी की रूपरेखा की एक दृष्टिगोचर मजबूत खासियत है। यह परियोजना महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों सहित जनसंख्या के वंचित वर्गों के अधिकारों एवं जीवनयापन के अवसरों को बढ़ाने के लिए उड़ीसा सरकार के मौजूदा प्रयासों के लिए सहायता प्रदान करेगी।"*

इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्र क्शन एंड डेवलेपमेंट की ओर से 150 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण 5 वर्ष की छूट अवधि के साथ 20 वर्ष में देय है।

विश्व बैंक के रियायती ऋण घटक इंटरनेशनल डेवलेपमेंट एसोसिएशन की ओर से 75 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के लिए 0.75 सेवा शुल्क लागू है तथा 10 वर्ष की छूट अवधि और 35 वर्ष की परिपक्वता अवधि है।

कृपया भारत में विश्व बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: *http://www.worldbank.org.in*

कृपया परियोजना संबंधी अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=P097036